भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2982

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

.....

नदियों को आपस में जोड़ा जाना

2982. श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में नदियों को आपस में जोडने की प्रक्रिया में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का नेपाल से बिहार की ओर नीचे प्रवाहित होने वाली पर्वतीय नदियों को राज्य की किसी अन्य नदी से मिलाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नदियों को आपस में जोडने का कार्य करने के लिए राज्य सरकारों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं या उस पर हस्ताक्षर करने पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नदियों को आपस में जोड़ने की इस परियोजना पर कितना अनुमानित व्यय होगा तथा अनुमानित कितना समय लगेगा?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

:(क) भारत सरकार ने 1980 में नदियों को जोड़ने (आईएलआर) के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत नदियों को जोड़ने का काम सौंपा गया है। एनपीपी के दो घटक हैं, अर्थात् हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक। एनपीपी के तहत 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है। पिछले 5 वर्षों में, आईएलआर कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसका विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है

(ख) और (ग): एनपीपी के हिमालयी नदियों के विकास घटक के तहत, 3 लिंक परियोजनाएं, अर्थात; कोसी-मेची लिंक परियोजना, कोसी-घाघरा लिंक परियोजना और चुनार-सोन बैराज लिंक परियोजना में नेपाल से बहने वाली कोसी, घाघरा और गंडक नदियों के पानी को बिहार राज्य की अन्य नदियों में अंतरित करने की परिकल्पना की गई है।

एनडब्ल्यूडीए द्वारा कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) पूरी कर ली गई है। यह लिंक परियोजना नेपाल में स्थित है। पीएफआर के अनुसार, यह लिंक 4.74 लाख हेक्टेयर (बिहार में 2.99 लाख हेक्टेयर) की वार्षिक सिंचाई और बिहार और नेपाल में 24 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति प्रदान करेगा।

कोसी-घाघरा लिंक परियोजना,जिसके लिए मसौदा व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) पूरी कर ली गई है, बिहार और उत्तर प्रदेश (यूपी), कोसी, कमला, बलान, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा नदियों के घाटियों में गंगा नदी

के उत्तर में असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई का विस्तार करने के लिए प्रस्तावित चतरा बैराज से घाघरा तक कोसी नदी के दाहिने किनारे से 7482 एमसीएम जल के अंतरण की परिकल्पना की गई है। यह लिंक 10.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (बिहार में 8.17 लाख हेक्टेयर) को वार्षिक सिंचाई और बिहार, यूपी और नेपाल में 48 एमसीएम घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति प्रदान करेगा।

चुनार-सोन बैराज लिंक परियोजना, जिसके लिए एफआर का मसौदा पूरा हो चुका है, द्वारा चुनार में गंगा नदी से सोन नदी तक जल के अंतरण की परिकल्पना की गई है। चुनार में गंगा नदी प्रस्तावित गंडक-गंगा लिंक परियोजना से 6879 एमसीएम और प्रस्तावित घाघरा-यमुना लिंक परियोजना से 4090 एमसीएम जल की वृद्धि के माध्यम से अतिरिक्त होगी। इस अधिशेष में से सोन नदी में मोड़ने के लिए चुनार में उपलब्ध गंगा जल 5918 एमसीएम होगा। यह लिंक परियोजना मार्ग में 0.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई के लिए प्रदान करेगी, जिसमें से 0.13 लाख हेक्टेयर बिहार में स्थित है। लिंक नहर 4364.49 एमसीएम पानी की सीमा तक वेस्टर्न सोन लो लेवल कैनाल और हाई लेवल कैनाल के मौजूदा कमांड को अधिग्रहीत कर लेगी और सोन बैराज की 928.47 एमसीएम जल की मौजूदा आवश्यकता को भी सीधे अधिग्रहीत कर लेगी। इस व्यवस्था के कारण, सोन बांध-गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियों के माध्यम से बिहार को अतिरिक्त 2.99 लाख हेक्टेयर सिंचाई भी प्रदान की जाएगी, जिसका पीएफआर पूरा हो चुका है।

उपर्युक्त के अलावा, कोसी-मेची अंतर-राज्यीय संपर्क परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मार्च, 2014 में एनडब्ल्यूडीए द्वारा तैयार की गई थी। अंतर-राज्य लिंक परियोजना को क्रमशः 2019 और 2020 में पर्यावरणीय मंजूरी और निवेश मंजूरी दी गई है। इस अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए एनडब्ल्यूडीए और बिहार सरकार के बीच दिसंबर, 2022 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) और (ङ): सरकार ने आईएलआर कार्यक्रम को परामर्शी तरीके से आगे बढ़ाया है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आईएलआर परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पक्षकार राज्यों को भेजी जाती हैं और जल बंटवारे आदि से संबंधित मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाते हैं ताकि इन संपर्क परियोजनाओं को कार्यान्वयन चरण में आगे ले जाया जा सके।

केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) एनपीपी के तहत पहली आईएलआर परियोजना है, जिसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। पक्षकार राज्यों और भारत सरकार के बीच केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओए) पर 22.03.2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद, लिंक परियोजना को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) अर्थात केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के माध्यम से दिसंबर, 2021 में भारत सरकार द्वारा 39,317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 44,605 करोड़ रुपये (वर्ष 2020-21 मूल्य स्तर) की अनुमानित लागत पर कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था। केबीएलपी (चरण 1 और चरण 2) पर अब तक किया गया कुल व्यय 7998.42 करोड़ रुपये है। इस लिंक परियोजना को मार्च, 2030 तक पूरा करने की योजना है।

अन्य आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के चरण में पहुंचने पर उनके पूरे होने के लिए व्यय और अनुमानित समय अवधि पर विचार किया जाएगा। तथापि, आईएलआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन आम सहमति पर पहुंचने के लिए पक्षकार राज्यों पर निर्भर करता है।

*****

अनुलग्नक

"नदियों को आपस में जोड़ा जाना" के संबंध में दिनांक 06.02.2023 को राज्य सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2982 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले 5 वर्षों में नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) कार्यक्रम में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का ब्यौरा:

1. 1 लिंक परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर), 9 लिंक परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और 7 लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी हो चुकी हैं।

2. केन-बेतवा लिंक परियोजना एनपीपी के तहत पहली लिंक परियोजना है, जिसके लिए कार्यान्वयन दिसंबर, 2021 में भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वर्ष 2022 में शुरू किया गया है। लिंक परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक स्वीकृति और अधिकांश सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं।

3. पार-तापी-नर्मदा लिंक और दमनगंगा-पिंजाल लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मसौदा तैयार किया गया था और सितंबर, 2017 में महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों को भेजा गया था।

4. गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना (जिसमें तीन लिंक परियोजनाएं शामिल हैं) के लिए डीपीआर एनडब्ल्यूडीए द्वारा पूरा किया गया था और अप्रैल, 2021 में संबंधित राज्यों को भेजा गया था। पक्षकार राज्यों के साथ फरवरी, 2022 में हुई परामर्श बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना के लिए एक वैकल्पिक अध्ययन एनडब्ल्यूडीए द्वारा पूरा कर लिया गया है और इसके लिए एक तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीएफआर) जनवरी, 2023 में पक्षकार राज्यों को प्रस्तुत की गई है।

5. नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति की दिनांक 13.12.2022 को हुई बैठक में संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक के चरण-I को एनपीपी के भाग के रूप में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ विधिवत एकीकृत करने और इस परियोजना को प्राथमिकता लिंक परियोजनाओं में से एक घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के लिए मसौदा पीएफआर और मसौदा समझौता ज्ञापन पूरा हो गया है और जनवरी, 2023 में संबंधित राज्यों को भेज दिया गया है।

6. महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के लिए सिस्टम अध्ययन भी पूरा कर लिया गया है।

*****